of a 3 MMTPA capacity grass-root refinery at Mangalore as a Joint Venture, between HPC1 and Indian Rayon Industries Limited. The implementation of the Mangalore Refinery project is in progress and actual physical progress as on September, 1995 was about 90%.

(b) The project is expected to be completed by June, 1996.

(c) The revised estimated cost is about Rs. 2593 crores, including FE component of Rs. 944.20 crores.

'Plundering of Money by Van Vibhag in U.P.'

2387. MAULANA OBAIDULLAH KHAN AZMI: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Government are aware that Van Vibhag in all the districts in U.P. are involved in plundering money and are doing little towards environment and forests; and

(b) if so, the steps being taken in the matter?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI RAJESH PILOT): (a) and (b) The information is being sought from the State Government of UP and will be laid on the Tabic of the House.

Payment of Environmental Rent

2388. SHRI SANJAY DALMIA: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether India has demanded that Western countries should pay "environmental rent" for the excessive emission of Green House cases;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the reaction of the Western countries on this demand?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI RAJESH PILOT): (a) and (b) The argument pertaining to environment rent' has been advanced by India in the nature of stressing the point that the developed nations have excessively utilised the common resource of atmosphere in the past and continue to do so. The estimates of the 'environmental rent' worked out by Indian researchers are of the order of US dollars 70 billion equivalent per year.

(c) Western countries have not formally made known their reaction.

मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में संचार सुविधायें उपलब्ध करना

2389. **श्री अजीत जोगी**: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश के पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु कोई योजना केन्द्रीय सरकार को भेजी हैं;

(ख) यदि हां,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;और

(ग) उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

पत्तनों में गाद का भरना

2390. **श्री नरेश यादव**: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न पत्तनों में समुद्र तल में भर रही गाद को निकालने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रबंध किये गये हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार के पास इस प्रयोजनार्थ कोई तंत्र हैं;और

(ग) यदि नहीं तो भारत सरकार ने किन-किन देशों को इस कार्य के संबंध में ठेका दिया हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम.राजशेखर मूर्ति): (क) और (ख) भारत सरकार ने देश में विभिन्न पत्तनों की निकर्षण संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के एक उपक्रम,भारतीय निकर्षण निगम(डी.सी.आई) की स्थापना की हैं। इसके अतिरिक्त ,कुछेक महापत्तनों को उनके नियंत्रण में आने वाले क्षेत्र से गाद निकालने के लिए निकर्षण उपकरण उपलब्ध करवाए गए हैं।

।

(ग) डी.सी.आई तथा पत्तनों की क्षमता से ज्यादा अतिरिक्त निकर्षण संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए निम्नलिखित विदेशी फर्मो को अनुरक्षण निकर्षण हेतु ठेके दिए गए हैं:-

1. बम्बई पत्तन तथा नव मंगलूर पत्तर में नीदरलैंड की मैं.हैम.,और

2. मूरगांव पत्तन में नीदरलैंड की मैं.वान ऊर्ड ।

ग्रामीण क्षेत्रों में डाक वितरण प्रणाली की समीक्षा करना

2391. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला**:

श्री ईश दत्त यादव:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में डाक वितरण प्रणाली की समीक्षा की हैं;

(ख) यदि हां,तो इसके क्या परिणाम निकले हैं;और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) डाक सर्किल अध्यक्षों तथा अन्य फील्ड अधिकारियों द्वारा डाक वितरण प्रणाली की सामान्यतया और ग्रामीण क्षेत्रों की डाक वितरण प्रणाली की विशेष रूप से निरंतर मॉनीटरिंग व आवधिक पुनरीक्षा की जाती हैं ।

(ख) और (ग) अंत: जिले की डाक का एक बड़ा भाग,जो मुख्यत: ग्रामीण क्षेत्रों की डाक होती हैं,पोस्ट किए जाने वाले दिन के बाद से 48 घंटों के भीतर वितरित कर दी जाती हैं । तथापि,ट्रांसपोर्ट में विलंब और विभाग के नियंत्रण से बाहर अन्य कारणों से यदा-कदा होने वाले विंलब से इंकार नहीं किया जा सकता । जब भी ग्रामीण डाक वितरण से संबंधित कोई समस्या ध्यान में आती हैं,उसे दूर करने के लिए सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं ।

Violation of Human Rights in USA

2392. SHRI SUSHILKUMAR SAMBHA.TIRAO SHINDE:
SHRIMATI VEENA VERMA:

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the preceding year's report of Amnesty International about the rampant violations of human rights against ethnic minorities in U.S.A.;

(b) if so, what are the main reports involving NRIs and Americans of Indian Origin in USA that have come to Government's notice as per Amnesty International report and other-wise during 1993-94, 1994-95 and so far in 1995-96; and

(c) what is Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI PRANAB MUKHERJEE): (a) and (b) While the Amnesty International Reports for the years 1993, 1994 and 1995 do cover specific instances of violation of human rights of ethnic minorities, particularly Blacks and Hispanics, they do not report any instance of such violation of rights of NRIs or Americans of Indian origin.

(c) Under the circumstances, there is no reason for the Government of India to react to these Reports.

Scarcity of LPG in Orissa and Bihar

2393. SHRI JANARDAN YADAV: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be please to state:

(a) whether Government are aware of the scarcity of LPG in Orissa and Bihar;

(b) if so, the steps taken to open new LPG agencies in those States;

(c) whether places have been identified for the location of LPG agencies in these States;

(d) if so, whether any such place has